

भारत सरकार
आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 809
24, जुलाई 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

उत्तर प्रदेश में शहरी विकास के लिए नई परियोजनाएँ

809. श्री सनातन पांडेय:

क्या आवासन और शहरी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने हाल ही में उत्तर प्रदेश में विशेष रूप से बलिया लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र में बुनियादी ढांचे, शहरी विकास और सामुदायिक सेवाओं को बढ़ाने के लिए नई परियोजनाओं को मंजूरी दी है या शुरू किया है; और

(ख) यदि हां, तो इसके लिए आवंटित बजट, परियोजना की समय-सीमा और स्थानीय आबादी को संभावित लाभसहित जिलावार ब्यौरा क्या है?

उत्तर
आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री
(श्री तोखन साहू)

(क) और (ख) सातवीं और बारहवीं अनुसूची के संयोजन में संविधान के अनुच्छेद 243 डब्ल्यू के उपबंधों के अनुसार, शहरी विकास से संबंधित मामले राज्यों/शहरी स्थानीय निकायों के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। हालांकि, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (एमओएचयूए) अपने विभिन्न प्रमुख मिशनों/ कार्यक्रमों जैसे अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन 2.0 (अमृत 2.0), प्रधानमंत्री आवास योजना - शहरी 2.0 (पीएमएवाई-यू 2.0), स्वच्छ भारत मिशन - शहरी 2.0 (एसबीएम-यू 2.0), प्रधानमंत्री पथ विक्रेता आत्मनिर्भर निधि (पीएम स्वनिधि), शहरी परिवहन (यूटी), आदि के माध्यम से राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) को उनके शहरी विकास एजेंडे में कार्यक्रम संबंधी सहायता प्रदान करता है।

इन मिशनों/योजनाओं के माध्यम से, केंद्र सरकार राज्य योजनाओं को अनुमोदित करती है और राज्यों को केंद्रीय सहायता (सीए) प्रदान करती है। परियोजनाओं का चयन, डिजाइन, अनुमोदन और क्रियान्वयन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों और शहरों द्वारा किया जाता है। राज्य सरकारें शहरों/जिलों को निधियां जारी करती हैं।

एसबीएम-यू : भारत सरकार ने 2 अक्टूबर, 2014 को स्वच्छ भारत मिशन-शहरी (एसबीएम-यू) की शुरुआत की थी। इसका उद्देश्य सभी शहरों को खुले में शौच से मुक्त (ओडीएफ) बनाना और बलिया लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र सहित सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के शहरी क्षेत्रों में उत्पन्न नगरपालिका ठोस अपशिष्ट (एमएसडब्ल्यू) का 100% वैज्ञानिक प्रसंस्करण करना था। इस प्रगति को आगे बढ़ाने के लिए, 1 अक्टूबर, 2021 को एसबीएम-यू 2.0 का शुभारंभ किया गया है। इसका उद्देश्य 100% स्रोत पृथक्करण, घर-घर जाकर संग्रहण और वैज्ञानिक लैंडफिल में सुरक्षित निपटान सहित कचरे के सभी अंशों के वैज्ञानिक प्रबंधन के माध्यम से सभी शहरों को कचरा मुक्त बनाना है।

स्वच्छ भारत मिशन - शहरी (एसबीएम-यू) के तहत, भारत सरकार द्वारा राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों को निधियाँ, राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा प्रस्तुत राज्य स्तरीय तकनीकी समिति (एसएलटीसी) द्वारा विधिवत अनुमोदित कार्य योजना के आधार पर जारी की जाती है, जो संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार द्वारा शहरी स्थानीय निकायों को प्रदान की जाती है। अतः, स्वच्छ भारत मिशन (एसबीएम-यू) के अंतर्गत बलिया लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के संबंध में अनुमोदित वित्तीय सहायता/परियोजनाओं का विवरण उपलब्ध नहीं है। उत्तर प्रदेश को आवंटित निधियों का विवरण नीचे दिया गया है :

(₹ करोड़ में)

एसबीएम-यू (2014-2021)	एसबीएम-यू 2.0 (2021-2026)
1,740.98	4,073.80

इसके अतिरिक्त, स्वच्छता संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य का विषय है। देश के शहरी क्षेत्रों में स्वच्छता परियोजनाओं की योजना बनाना, डिजाइन करना, क्रियान्वयन और संचालन करना राज्य/शहरी स्थानीय निकायों की ज़िम्मेदारी है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा एसबीएम-यू के अंतर्गत प्रस्तुत सभी परियोजनाओं का विवरण एसबीएम-यू, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के पोर्टल <https://sbmurban.org/swachh-bharat-mission-progress> पर उपलब्ध है।

अमृत : अमृत 2.0 का शुभारंभ 1 अक्टूबर 2021 को किया गया था। अमृत 2.0 का उद्देश्य शहरों को 'आत्मनिर्भर' और 'जल सुरक्षित' बनाना है। 500 अमृत शहरों में सीवरेज और सेप्टेज प्रबंधन की यूनिवर्सल कवरेज प्रदान करना अमृत 2.0 का एक अन्य प्रमुख लक्ष्य है।

जलाशयों का नवीकरण और हरित क्षेत्रों व पार्कों का विकास इस मिशन के अन्य घटक हैं। अमृत 2.0 के तहत अब तक उत्तर प्रदेश में आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा 26,758.53 करोड़ रुपये (संचालन एवं रखरखाव लागत सहित) की कुल 655 परियोजनाओं को अनुमोदित किया जा चुका है। जिले-वार विवरण अनुलग्नक I में दिया गया है।

अमृत 2.0 के तहत बलिया लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में अब तक 442.73 करोड़ रुपये की 03 परियोजनाओं को अनुमोदित किया जा चुका है, जिनमें 172.07 करोड़ रुपये की 02 जलापूर्ति परियोजनाएँ और 270.67 करोड़ रुपये की एक सीवरेज/सेप्टेज प्रबंधन परियोजना शामिल है। अमृत और अमृत 2.0 के तहत, केंद्रीय निधियाँ राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) को आवंटित/जारी की जाती हैं, जिले-वार जारी नहीं की जाती। उत्तर प्रदेश में अमृत 2.0 के तहत, परियोजनाओं के लिए 8,161 करोड़ रुपये के केंद्रीय हिस्से की तुलना में 1,896.68 करोड़ रुपये जारी/स्वीकृत किए जा चुके हैं।

'उत्तर प्रदेश में शहरी विकास के लिए नई परियोजनाएँ' के संबंध में दिनांक 24 जुलाई, 2025 को पूछे जाने वाले लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 809 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक ।

अमृत 2.0 के तहत उत्तर प्रदेश में जिले-वार स्वीकृत परियोजनाएँ

क्र. सं.	जिला	अनुमोदित परियोजनाएँ	
		सं.	अनुमानित कुल परियोजना लागत (करोड़ रुपये में)
1	आगरा	15	742.42
2	अलीगढ़	16	555.18
3	अंबेडकर नगर	10	221.57
4	अमेठी	3	94.00
5	अमरोहा	10	151.23
6	औरिया	6	191.90
7	अयोध्या	19	1,342.26
8	आजमगढ़	5	185.25
9	बागपत	6	318.12
10	बहराइच	6	232.84
11	बलिया	8	544.49
12	बलरामपुर	4	211.98
13	बाँदा	14	347.20
14	बाराबंकी	7	300.92
15	बरेली	14	278.09
16	बस्ती	5	90.88
17	भदोही	2	125.71
18	बिजनौर	8	318.65
19	बदायूँ	10	288.30
20	बुलंदशहर	17	332.79
21	चंदौली	6	118.38
22	चित्रकूट	8	362.40
23	देवरिया	6	102.08
24	एटा	6	222.14
25	इटावा	8	352.05
26	फर्रुखाबाद	5	191.64
27	फतेहपुर	15	664.90
28	फिरोजाबाद	3	32.45
29	गौतम बुद्ध नगर	7	94.53
30	गाजियाबाद	20	1,258.25
31	गाजीपुर	3	127.93
32	गोंडा	7	134.10
33	गोरखपुर	19	2,447.16
34	हमीरपुर	9	269.03
35	हापुड	9	107.87
36	हरदोई	10	307.08
37	हाथरस	6	186.98

क्र. सं.	जिला	अनुमोदित परियोजनाएँ	
		सं.	अनुमानित कुल परियोजना लागत (करोड़ रुपये में)
38	जालौन	18	818.19
39	जौनपुर	6	351.14
40	झांसी	18	466.16
41	कन्नौज	4	92.82
42	कानपुर	11	1,465.81
43	कानपुर देहात	4	130.20
44	कासगंज	4	81.73
45	कौशांबी	4	123.61
46	खीरी	7	215.50
47	कुशीनगर	7	211.10
48	ललितपुर	7	197.68
49	लखनऊ	19	1,351.55
50	महाराजगंज	3	94.75
51	महोबा	5	272.03
52	मैनपुरी	3	178.72
53	मथुरा	10	360.85
54	मऊ	4	377.88
55	मेरठ	23	501.85
56	मिर्जापुर-सह-विंध्याचल	9	229.56
57	मुरादाबाद	11	436.89
58	मुजफ्फरनगर	7	325.78
59	पीलीभीत	11	139.07
60	प्रतापगढ़	5	217.50
61	प्रयागराज	11	773.82
62	रायबरेली	8	221.75
63	रामपुर	9	161.84
64	सहारनपुर	9	257.33
65	संभल	7	202.13
66	संत कबीर नगर	3	137.71
67	शाहजहांपुर	12	304.63
68	शामली	4	199.28
69	सिद्धार्थनगर	11	321.00
70	सीतापुर	8	174.10
71	सोनभद्र	10	519.02
72	श्रावस्ती	2	83.53
73	सुल्तानपुर	6	65.34
74	उन्नाव	9	209.05
75	वाराणसी	14	634.88
	कुल	655	26,758.53
